SHRI ARUN KUMAR NEHRU : These matters are under discussion already. Let the discussions be over and then we will analyse the situation and see what should be done.

MR. CHAIRMAN : All right. Question No. 462.

Completion of Godavary and Krishna Valley Projects

*402. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV :

SHRI JAGESH DESAI :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what are the on going projects of Godavary and Krishna Valley in the States of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh;

(b) what are the financial arrangements for these projects; and

(c) what is the time schedule of their completion ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है । **(नीचे देखिए)**

(ख) राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण अपने बजट संबंधी संसाधनों के अन्तर्गत किया जाता है । कर्नाटक में अपर कृष्णा परियोजना चरण-1 महाराष्ट्र में जयाकवाडी परियोजना चरण-1 और 2 तथा आन्ध्र प्रदेश में श्रीराम सागर और श्री सेलम दायां तट नहर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक सहायता की भी व्यवस्था की गयी है ।

(ग) सभा पटल पर रखे गए विवरण के कालम 3 में सूचना दी गयी है ।

विवरण

गोदावरी तथा कृष्णा बेसिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश में निर्माणाधीन अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3
	(क) गोदावरी बेसिन	
1.	**महाराष्ट्र**	
(क)	**बृहद परियोजनाएं**	
(1)	जायकवाडी परियोजना चरण-1 और 2	आठवीं योजना
(2)	अपर गोदावरी	आठवीं योजना
(3)	लोअर त्रिना	आठवीं योजना
(4)	विष्णु पुरी	आठवीं योजना
(5)	अपर पेनगंगा	आठवीं योजना के बाद
(6)	अपर वर्धा	आठवीं योजना के बाद
(7)	पेन्च	पूरी हो गई है
(8)	कालीसरार	आठवीं योजना
(9)	अपर परावारा	आठवीं योजना के बाद
(10)	नन्दूर माधनेश्वर	आठवीं योजना के बाद
(11)	लोअर दुधना	आठवीं योजना के बाद
(12)	मन्जरा	पूरी हो गई है

1	2	3
(ख)	**मध्यम परियोजनाएं**	
(1)	कोराडी	पूरी हो गई है
(2)	अरन (पिपरी बार्वत)	आठवीं योजना
(3)	वागदी	पूरी हो गई है
(4)	धाम	आठवीं योजना
(5)	दोंगरागांव (नान्देड)	पूरी हो गई है
(6)	अंजना पल्सि	आठवीं योजना
(7)	पूरना नेओपूर	आठवीं योजना
(8)	पेंधारी नाला	आठवीं योजना
(9)	कार्वापा नाला	आठवीं योजना
(10)	पाकतीगुदाम	आठवीं योजना
(11)	दिओर्जन	आठवीं योजना
(12)	अमल नाला	पूरी हो गई है
(13)	गोकी	पूरी हो गई है
(14)	लोअर पस	आठवीं योजना
(15)	कोलार	आठवीं योजना
(16)	खे-खेरा नाला	आठवीं योजना
(17)	बोरगांव टैंक	आठवीं योजना
(18)	रुई	आठवीं योजना
2.	**कर्नाटक**	
(क)	**बृहद परियोजनाएं**	
	—शून्य—	
(ख)	**मध्यम परियोजनाएं**	
(1)	चुल्किनाला	आठवीं योजना
3.	**आन्ध्र प्रदेश**	
(क)	**बृहद परियोजनाएं**	
(1)	श्री रामसागर परियोजना	3/94
(2)	सिन्नूर	3/92
(3)	गोदावरी	3/91
(ख)	**मध्यम परियोजनाएं**	
(1)	थान्दवा रिजर्वोयर	3/93
(2)	रायवाडा	3/91
(3)	वोत्तिवगु	3/95
(4)	बगुलावगु	3/91
(5)	मद्दुयालसा	3/95

1	2	3
(6)	तालीपेरू	3/95
(7)	गुण्डालाकेरु	3/92
(8)	सतनाला	3/95
(9)	मड्डिगड्डा	3/91
(10)	आन्ध्र रिजर्वायर आक्रोस चम्पावती	3/93
(11)	कोनम	3/91
(12)	मुकामामिदि	उपलब्ध नहीं
(13)	जालेरू	3/91

(ख) **कृष्णा बेसिन**

1. **महाराष्ट्र**

(क) **बृहद परियोजनाएं**

(1)	कुकाडी	आठवीं योजना के बाद
(2)	भीमा	आठवीं योजना
(3)	वर्ना	आठवीं योजना के बाद
(4)	खडकवासला	आठवीं योजना
(5)	कृष्णा	आठवीं योजना के बाद
(6)	चास्कामन	आठवीं योजना के बाद

(ख) **मध्यम परियोजनाएं**

(1)	चिकोत्रा	आठवीं योजना
(2)	कसारी	आठवीं योजना
(3)	कुम्भी	आठवीं योजना
(4)	कादवी	आठवीं योजना
(5)	वाडीवाले	आठवीं योजना
(6)	उर्मोदी	आठवीं योजना
(7)	संख	आठवीं योजना
(8)	पतगांव	आठवीं योजना
(9)	कोसरसाई	आठवीं योजना
(10)	सिना	आठवीं योजना
(11)	खैरी	आठवीं योजना
(12)	मोरूना	आठवीं योजना

2. **कर्नाटक**

(क) **बृहद परियोजनाएं**

(1)	अपर कृष्णा चरण-1	आठवीं योजना के बाद
(2)	तुंगभद्रा एल.बी.सी. और बांध	आठवीं योजना
(3)	तुंगभद्रा आर.बी. एलएलसी	पूरी हो गई है
(4)	तुंगभद्रा आर.बी. एचएलसी	आठवीं योजना

1	2	3
	(5) भद्रा परियोजना	आठवीं योजना
	(6) घाटप्रभा चरण-3	आठवीं योजना के बाद
	(7) मालप्रभा	आठवीं योजना
	(ख) मध्यम परियोजनाएं	
	(1) अपर मुल्लामडी	आठवीं योजना
	(2) सौदागर	पूरी हो गई है
	(3) तीथा	पूरी हो गई है
	(4) अमरजा	आठवीं योजना
	(5) लोअर मुलामडी	आठवीं योजना
	(6) मास्किनाला	आठवीं योजना
	(7) हीरे नाला	आठवीं योजना
3.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	(क) बृहद परियोजनाएं	
	(1) नागार्जुनसागर	3/93
	(2) तुंगभद्रा एचएलसी चरण-2	3/93
	(3) श्रीसेलम आर बी सी	3/94
	(ख) मध्यम परियोजनाएं	
	(1) गुंटूर केनाल स्कीम एपी	3/91
	(2) पलिवेन्दुला केनाल	3/95
	(3) गाजुलादिन्नी	3/92
	(4) ओकाचेट्टीवेगु	3/91

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Sir, the honourable Minister has stated in his reply that the irrigation projects are funded by the State Governments from their own budgetary resources. The total irrigation potential of this country is 113 million hectares and, out of that, Maharashtra is having only 7.4 million hectares and the irrigation potential created in Maharashtra is only 3.8 million hectares which means just 3 per cent of the country's total irrigation potential. Maharashtra is a permanently drought prone State in the country since there are 113 talukas which come under the category of permanent drought-prone areas.

The question that I would like to ask the Minister is whether they are going to give priority to such States where the irrigation potential is already less and where the on-going projects have been going on for a number of years and they are not getting completed at all. I would like to know whether such on-going projects in Maharashtra—the list is given here—will be completed in the Eighth Plan at least.

श्री शरद यादव : सभापति जी, जो माननीय सदस्य जाधव जी ने कहा उससे मेरी सहमति है । इसमें दिक्कत अकेले केन्द्रीय सरकार की नहीं है । आपस में भी नदियों के बहुत झगड़े हैं और उनके चलते भी योजनाएं बहुत मंद हो जाती हैं, एक नया और शुरू हुआ है इन्वायरमेंट वाला जिसके चलते भी बड़ी दिक्कत पड़ रही है । यह मंत्रालय मेरा नहीं है लेकिन आज जब मैंने यह सब

देखा तो जवाब देने की बजाय मेरा मन है कि मैं इन्वायरमेंट पर भाषण दूं । मैं आपकी बात से सहमत हूं और वैसे महाराष्ट्र की . . . (व्यवधान) अभी आपकी कोई योजना यहां पेंडिंग नहीं है । जो योजनाएं चल रही हैं हमारी पूरी कोशिश है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में उनका कंप्लीशन हो जाए ।

कौन से प्रकल्प या कौन से इरीगेशन प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी पूरे किए जाएं, कब पूरे किए जाएं कैसे पूरे किए जाएं यह ज्यादा इरीगेशन डिपार्टमेंट खासकर हमारी केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के अंतर्गत होता है। हम सिर्फ एक तरह से लाएजन का काम करते हैं । पैसे और बजट का इंतजाम करना, जो खर्च है उसके अंतर्गत है । इन सारे कामों को तेज करने, गति देने का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का होता है । इरीगेशन सबसे ज्यादा निर्भर करता है स्टेट गवर्नमेंट के अपने कामों पर अपनी चीजों पर । दूसरा जो आपने कहा तो यहां से कोई कमी नहीं है । यहां से जितनी मेहनत होती है जितनी ताकत होती है वह आपके पक्ष में की जाती है और किसी स्टेट के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है ।

श्री सभापति : ये कह रहे हैं कि सब पैसे आदि की पूरी मदद आपको मिलेगी ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं । इन्होंने कहा कि प्रश्न इन्वायरमेंट का है । जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है इन्वायरमेंट का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सभापति : कोई प्रश्न ही नहीं है महाराष्ट्र में . . . (व्यवधान)

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : क्योंकि इन्वायरमेंट कन्ट्रोवर्सी जो चल रही है वह सरदार सरोवर के बारे में चल रही है । सरदार सरोवर के सिर्फ पावर जनरेशन संबंध महाराष्ट्र में है और सिंचाई का बहुत कम एरिया इसमें आता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो five major and seven medium projects in Krishna Basin and 11 major and 22 medium projects in Godavari Basin are pending with the Central Water Authority for a number of years, by when will they be cleared from the Central Water Authority ?

मेरा दूसरा "बी" पार्ट है कि कृष्णा बेसिन में प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए 1637 करोड़ की जरूरत है और गोदावरी बेसिन में सारे आन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए 2471 करोड़ रुपए की जरूरत है । टोटल हमको 1108 करोड़ रुपए की जरूरत है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 4108 करोड़ का प्रावधान ये करने वाले हैं या नहीं और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वे तुरन्त ही 6 महीने के अंदर क्लियर करने वाले हैं क्या ? यह बात मैं जानना चाहता हूं ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, कृष्णा बेसिन में ।

श्री सभापति : पहले यह बता दीजिए कि पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को आप कब तक क्लियर करेंगे । इन्होंने नम्बर बताये हैं कि इतने महाराष्ट्र के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं । उनको जल्दी कर दीजिए । जल्दी कोशिश करिये। 6 महीने में आप कर सकते हैं ? ये कह रहे हैं कि 6 महीने में कर दें ।

श्री शरद यादव : येस सर ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : इन्होंने दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया ।

श्री सभापति : दूसरा कृष्णा बेसिन के लिए पैसों का प्राविजन है ? वह जो इन्होंने उठाया है । वह दण्डवते जी से पूछ लीजिए फिर कहिएगा ।

श्री शरद यादव : एक बात आपने जो कही कि हमारे यहां कोई पेंडिंग योजना है । यहां कोई पेंडिंग योजना आपकी नहीं

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : नहीं नहीं । मैंने आपको दी है ।

श्री सभापति : वे कहते हैं कि गोदावरी वाटर पावर कमीशन में कोई पेंडिंग नहीं है ।

श्री प्रमोद महाजन : अगर पेंडिंग नहीं है तो क्लियर किसको करेंगे ।

श्री सभापति : वे पहले ही क्लियर्ड हैं ।

श्रीमती सूर्यकांता पाटिल : हमारे पास नम्बर है ।

श्री शरद यादव : महाराष्ट्र के जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट्स हैं, वह बारह लार्ज हैं और अठारह मीडियम हैं ।

श्री सभापति : आपने यह लिख दिया है। यह तो आपकी स्टेटमेंट में है ।

एक माननीय सदस्य : वह दुबारा पढ़ रहे हैं ।

श्री सभापति : इसके अतिरिक्त ?

श्री शरद यादव : गोदावरी में पांच लार्ज हैं और दो मीडियम हैं । वह अभी हम लोग एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे और उसके बाद देखेंगे । राज्य सरकार को जो वापिस किये गये हैं, वह पांच लार्ज है और उन्नीस मीडियम हैं ।

जो आपके यहां से क्लियर होकर फिर हमारे पास वापिस जाने हैं कंसिडरेशन के लिए, वह कम हैं ।

श्री सभापति : हैं ।

श्री शरद यादव : आपके यहां जो पड़े हुए हैं, वह ज्यादा हैं ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मान्यवर, मेरा सवाल था कि . . . (**व्यवधान**) ।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, my problem is this. Sharadji is a young dynamic Minister. I am aware of it But I want you to get the clarification from him. He has rightly asked the Minisetr a question. Will the provision for finances be made and are the projects cleared? He says: "Yes, Sir. Now the difficulty is that we are Member of the Rajya Sabha elected from State Assemblies. We are guided by the State Government's information.

MR. CHAIRMAN: Let him ask the question. We have to ask questions within the rules. Mr. Kulkarni, you are such a senior Member.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I am senior but the reply is very junior.

MR. CHAIRMAN: Let me maintain order in the House. I have called him. He will put the question. You can pass on your information to him in Marathi. I don't mind.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, let me make the position clear before the Minister answers. Five major and 7 medium projects in Krishna Basin and 11 major and 22 medium projects in Godavari Basin are pending with the Central Water Authority. I want to know whether these projects will be cleared within a period of six months. Secondly, the total requirement of finances for the on-going projects is 4108 crores of rupees. Unless you make provision, from where will the Maharashtra Government spent this money. I want to know whether in the Eighth Five-Year Plan you are going to give these 4000 crores of rupees worth of funds to the Maharashtra Government for completion of on-going projects. This is my question. (*Interruptions*).

श्री सभापति : क्या आपने मधु दण्डवते जी से बात कर ली है ?

श्री शरद यादव : महोदय, मेरी मुश्किल यह हो रही है कि जाधव जी पूछ रहे हैं और दादा भी पूछ रहे हैं, जोकि भारी आदमी हैं, ज्ञानी . . . (**व्यवधान**) ।

श्री प्रमोद महाजन : यह गोदावरी के हैं और वह कृष्णा के हैं । इसलिए दोनों मिल कर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : यह महाराष्ट्र की समस्या है । सर, हमें गोदावरी और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है।

हम सब महाराष्ट्र के हैं । गोदावरी, कृष्णा का वहां संगम है ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : आप लोग पैसा देते हैं । . . . (*व्यवधान*) ।

श्री शरद यादव : मेरा कहना यह है कि . . . (*व्यवधान*) ।

श्री सभापति : इस सवाल पर आधा घंटा होने को हो गया है ।

श्री शरद यादव : जिस फाइनेंशल मदद के बारे में जाधव जी कह रहे हैं, उसमें हम कोई कसर नहीं रखेंगे । जो हमारी ताकत होगी और जो उचित काम होगा, वह किया जाएगा ।

श्री सभापति : वह काम करेंगे ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हम आठवीं योजना का पूछ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि जो उचित होगा, वह काम करेंगे।

SHRI JAGESH DESAI : Mr. Chairman, Sir, most of the revenue which the Central Government gets is from Excise and from Customs. These are the major sources of revenue. In Maharashtra, the total land irrigated is 11 per cent only whereas the average in the country is 25 per cent.

MR CHAIRMAN : This is irrigation.

SHRI JAGESH DESAI : Yes, Sir. So, I would request the Government that they should give to Maharashtra a larger sum for the purpose of irrigation. Now it has been said in the answer that it has become one the major projects of Krishna Basin and all will be completed beyond the Eighth Five Year Plan

None of them would be completed in the Eighth Plan or beyond the Eighth Plan. As regards the Godavari Basin, 5 will be completed within the Eighth Five Year Plan and five will be completed beyond the Eighth Plan Sir, Eighth Plan is not yet finalised till today. We are in the month of September and it has not been finalised yet. So, I would like to know from the Government as to how much amount you have provided for the proposals which you have given to the Planning Commission for the projects which are to be completed in the Eighth Plan for the Krishna Basin. And for the Godavari Basin, for the major projects, how much have you provided

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, देसाई जी ने जो पूछा है कि प्लानिंग कमीशन करेगा और कितना करेगा ? वह तो मेरे पास जानकारी नहीं है ।

SHRI JAGESH DESAI : You have said that you will be completing in the Eighth Plan. I want to know that amounts you have provided.

MR. CHAIRMAN : He will require notice for it.

श्री शरद यादव : मेरी सुनिए, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं ? अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा, पहले भी कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को हम लोग यहां से फायनेंसियल, दूसरे, प्लानिंग कमीशन से, वर्ल्ड बैंक से जिस तरह की मदद करते हैं, वह पूरी मदद स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती है । यहां से जो हम लोगों के लिए संभव है वह हम लोग कर रहे हैं । जो कम्पलीट हैं, उसमें मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास इनफारमेशन नहीं है । लेकिन जो आपने पूछा कि प्लानिंग कमीशन में जो देरी हो रही है, उसे कब तक पूरा किया जाएगा इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग इसमें जल्दबाजी करेंगे कि ये योजनाएं अपने वक्त के अनुसार पूरी हों, इसके लिए हम लोग पूरी तरह सजग हैं ।

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN : Sir, we are all aware of the fact that very often the Godavari and the Krishna are in floods. These floods have become an annual feature. They not only devastate a number of villages but also damage a lot of crops. At the same time, in Tamil Nadu, we are starving of water. If enough water is provided to Tamil Nadu, we could go for optimum production. In order to attain this achievement I

want to know whether the Government will come forward to link the Mahanadi, the Godavari and the Krishna by a system of canals, and ultimately this system of canals may be linked to the Cauvery so that they could provide enough water facilities to Tamil Nadu.

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, यह जो सवाल है यह तो सिर्फ कर्नाटक, आन्ध्र और महाराष्ट्र--इन तीनों के प्रोजेक्ट के बारे में है और माननीय सदस्य ने तमिलनाडु की ड्रिंकिंग वाटर से लेकर वहां के सवाल उठाए हैं । अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि आज मैं इस सवाल को ही पढ़कर आया हूं । . . . **(व्यवधान)** ।

श्री सभापति : बिल्कुल सही कह दिया है ।

श्री शरद यादव : मैं व्यापक उत्तर जरूर देता, लेकिन आज तो इस सवाल से यह सवाल उठता ही नहीं । इसलिए मैं माफी चाहता हूं । जवाब तो मैं देता आपको पूरा, लेकिन मैं तो इसी को देखकर आया हूं ।

श्री सभापति : गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को मिलाना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : वैसे जिस प्रकार आप जवाब दे रहे हैं, इसका भी दे दीजिए ।

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN : Sir, we want a Short Duration Discussion on this.

MR. CHAIRMAN : You write to me. I will see.

श्री शरद यादव : सभापति जी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने की योजना का सर्वेक्षण चल रहा है यानी जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं सरकार उस सपने को धरती पर उतारने के लिए सर्वेक्षण कर रही है ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY : Sir, the Bachawat Award allotted 800 TMC ft. of water to Andhra Pradesh, 700 TMC ft. to Karnataka and 560 TMC ft. to Maharashtra from the assured water of Krishna river. But there is an apprehension in the minds of the people of Andhra Pradesh that the States of Maharashtra and Karnataka are utilising the Krishna water, more than the quantity allotted to them, by constructing several medium and minor irrigation projects without the knowledge of the Central Water Commission. I would like to know whether it is a fact? If it is a fact, what action the Government of India is going to take?

श्री शरद यादव : सभापति जी, अभी तीन मुख्य मंत्री जो हैं, वह कुछ दिन पहले ही, क्योंकि इस पर तीनों मुख्य मंत्री कर्नाटक के, आन्ध्र प्रदेश के और महाराष्ट्र के यह कृष्णा-गोदावरी के जो वाटर डिसप्यूट्स हैं इस पर तीनों ने हम लोगों से कहा है कि हम लोग आपस में ही इन चीजों को तय करके आपको देंगे और कुछ बातें उन्होंने तय भी की हैं । इसी तरह माननीय सदस्य तुलसी रेड्डी जी ने जो कहा है, एनक्रोचमेंट तो सभी कर रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों का यह ख्याल है कि आन्ध्र प्रदेश के लोग बहुत एनक्रोचमेंट कर लिए हैं बहुत से कंस्ट्रक्शन, बहुत सा कृष्णा पर और गोदावरी पर . . . . **(व्यवधान)** ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY : Andhra Pradesh is a riparian State.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Andhra Pradesh is in the tailend. Therefore, there is no question of encroachment by Andhra Pradesh. Only the States upstream can do so. What the hon. Minister saying is not correct. Either Maharashtra or Karnataka may be encroaching.

DR. NARREDDY THULASI REDDY : How can Andhra Pradesh encroach?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Sir, the word 'encroachment' is highly objectionable. He should use some other word.

श्री शरद यादव : एक और जो माननीय सदस्य ने कहा कि यह एनक्रोचमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, यानी कृष्णा घाटी में जो परियोजनाएं कर्नाटक और महाराष्ट्र में बन रही हैं यह निर्धारित पानी के हकदार से

ज्यादा नहीं है, जो समझौता है उसी के अनुसार वह परियोजनाएं बन रही हैं ।

*403. [*The questioner (Shri S. S. Ahluwalia) was absent. For answer Vide cols.* 36-37 *infra.*]

Public Financial Institutions Operating in the Country

*404. SHRI YASHWANT SINHA : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) what are the details of the public financial institutions operating in the country at present;

(b) what are the companies in which such public financial institutions hold 25 per cent or more share in equity capital: and

(c) in how many such companies; the institutions have their own nominees ?

THE FINANCE MINISTER (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Section 4 A of the Companies Act, 1956 specifies Industrial Credit & Investment Corporation of India (ICICI), Industrial Finance Corporation of India (IFCI), Industrial Development Bank of India (IDBI), Life Insurance Corporation of India (LIC) and Unit Trust of India (UTI) as Public Financial Institutions. Pursuant to the powers vested in the Central Government under this Section, Government has issued Notifications from time to time specifying Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI), General Insurance Corporation (GIC) and its four subsidiaries viz. National Insurance Co. Ltd., New India Assurance Co. Ltd., Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd. and United India Insurance Co. Ltd., Shipping Credit and Investment Company of India (SCICI), Tourism Finance Corporation of India (TFCI), Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd. (RCTC), Power Finance Corporation (PFC) and Technology Development and Information Company of India Ltd. (TDICI) as Public Financial Institutions.

(b) According to the information available with IDBI, there are 297 private sector companies in which public financial institutions along with State level Industrial Development Corporations (SIDCs), State Financial Corporations (SFCs), nationalised banks, Central and State Governments jointly hold 25% or more of equity capital of these companies. A list of these companies is given in the Annexure. [*See* Appendix CLV, Annexure No. 118.]

Statistics in respect of shareholdings of public financial institutions alone is not readily available.

(c) Out of the 297 companies, institutions have appointed their nominees on 231 companies.

SHRI YASHWANT SINHA : Sir, sometimes, we, Members of Parliament, get information which is tantalisingly brief as was happening just now. (*Interruptions*) Sometimes, we get information which we have not asked for. I think, whenever we deal with Dandavateji, this is the kind of thing which happens.

MR. CHAIRMAN : He is a professor. (*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : Sir, is it a censure or a compliment ?

PRO. MADHU DANDAVATE : Complement. In addition what he had asked for, I have given something more. This is what he means.

SHRI YASHWANT SINHA : Sir, if you read the question carefully, you will see that in part (a) of the question, I had asked for the names of the public financial institutions. Part (a) of the reply gives the names of the public financial institutions like the Industrial Credit and Investment Corporation of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, etc.

In part (b) of the question, I wanted to know which were the companies where such public financial institutions hold more than 25 per cent of the equity. The reply which has been given in part (b) talks not only of these public financial institutions but also about the State-